

‘चुनाव आयोग भाजपा का ‘ब्राँच ऑफिस’ हो गया है’

कांग्रेस के पद चिन्हों पर चलते हुए तृणमूल कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पर चढ़ाई की

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। कांग्रेस के बाद, तृणमूल कांग्रेस ने आज चुनाव आयोग पर भाजपा का शाखा कार्यालय होने का आरोप लगाया, क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ पार्टी के चुनावी अवसरों को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है।
दिल्ली में एक प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए राज्यसभा में टीएमसी के नेता डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि अगली साल होने वाले बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की संभावनाओं के बारे में पार्टी के आंतरिक आकलन के कारण ही चुनाव आयोग मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण को आगे बढ़ा रहा है।
डेरेक ओ' ब्रायन ने कहा, "भाजपा के नवीनतम आंतरिक सर्वेक्षण ने पार्टी को बंगाल में 46-49 सीटें दी हैं। यह (विशेष सघन पुनरीक्षण) उनकी तरफ से मामलों को अपने पक्ष में करने का एक हताशापूर्ण प्रयास है।"
तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी ने इस सप्ताह एक सार्वजनिक भाषण में बंगाल में भाजपा की 50 सीटों से कम की भविष्यवाणी की थी।

- राज्यसभा में तृणमूल कांग्रेस के नेता डैरेक ओ ब्राॅयन ने कहा कि ‘‘भाजपा के आंतरिक सर्वे व आंकलन के अनुसार, अगले साल बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा की 46-49 सीटें आने वाली हैं।
- ‘‘अतः चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में मतदाता सूची बनाने की प्रक्रिया में विशेष व गहरा परिवर्तन करना एक मजबूरी है भाजपा की, जिसमें चुनाव आयोग पूरा सहयोग कर रहा है।’’
- नई प्रक्रिया के अनुसार, उन मतदाताओं को, जिनका जन्म 1987 से पहले हुआ, मतदान से पूर्व अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जिनका जन्म 1987 व 2004 के बीच हुआ है, उन्हें न केवल अपना ‘‘बर्थ सर्टिफिकेट’’ बल्कि अपने माता-पिता का ‘‘बर्थ सर्टिफिकेट’’ भी दिखाना होगा।
- ‘‘क्या आप अपने माँ-बाप का बर्थ सर्टिफिकेट रखते हैं?’’ अतः यह तृणमूल की एक साजिश है, जिसमें ‘‘माइग्रैंट लेबर’’ आदि का मतदान का अधिकार खत्म करना है।
- डैरेक ओ ब्रायन का यह भी कहना है कि मतदान की प्रक्रिया में यह सघन परिवर्तन नाज़ी जर्मनी द्वारा 1935 में जारी किये ‘‘पूर्वज पास’’ (एन्सैस्टर पास) का नया रूप है, हम कहाँ जा रहे हैं।’’

राज्य सेवा के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार व अनुशासन के 3 8 प्रकरणों का निस्तारण

मुख्यमंत्री भजनलाल ने इन लंबित मामलों पर प्राथमिकता देते हुए निर्णय लिए

जयपुर, 28 जून। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशील, भ्रष्टाचार मुक्त एवं पारदर्शी सुशासन की नीति अपनाते हुए राज्य सेवा के अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति एवं 17-ए के विचाराधीन 38 प्रकरणों का निस्तारण किया है।
मुख्यमंत्री ने सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध लंबी अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं भ्रष्टाचार के 2 प्रकरणों में सेवा से हटाने एवं पदच्युत करने का निर्णय लिया है। वहीं अभियोजन स्वीकृति के लंबित प्रकरणों के निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 7 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की मंजूरी दी है। भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा 17-ए के 05 प्रकरणों में भी विस्तृत जांच एवं अनुसंधान करने की अनुमति भी प्रदान की है। इसी तरह

- राज्य सरकार ने 7 अधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति दी। धारा 17-ए के 5 प्रकरणों में विस्तृत जाँच की अनुमति प्रदान की। नौ सेवानिवृत्त अधिकारियों की पूर्ण आंशिक पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की।

11 सेवारत अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम-16 तथा 2 अधिकारियों के विरूद्ध सीसीए नियम-17 के तहत कार्यवाही करते हुए वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी/असंचयी प्रभाव से रोके

जाने के निर्णय किया है। इसके अतिरिक्त, सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 9 अधिकारियों की पूर्ण अथवा आंशिक पेंशन रोके जाने की कार्यवाही की गई है। वहीं 4 सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों के जांच निष्कर्ष का अनुमोदन किया गया है। साथ ही, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1 सेवानिवृत्त अधिकारी के विरूद्ध अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1969 के नियम 08 में प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन रोकने के दण्ड की अभिशंसा भारत सरकार को भिजवाई गई है। इसी तरह 2 प्रकरणों में सीसीए नियम 34 के तहत अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिकाओं को निरस्त करते हुए दण्ड को यथावत रखा गया है तथा विभागीय जांच के 2 प्रकरणों में आरोपित अधिकारियों को राहत दी गई है।

- प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला से कहा कि चंद्रयान की सफलता के बाद देश के युवाओं में विज्ञान के प्रति नई रुचि विकसित हुई है।

के बाद देश के युवाओं ने विज्ञान के प्रति एक नई रुचि विकसित की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रुप कैप्टन शुक्ला से कहा, आज आप हमारी मातृभूमि से दूर हैं, लेकिन आप भारतीयों के दिलों के सबसे करीब हैं। आपके नाम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोलकाता गैंग रेप की जाँच के लिए भाजपा ने पैनल बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 28 जून। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को कोलकाता के एक लॉ कॉलेज की छात्रा के गैंग रेप की घटना की निंदा की और इस धिनौनी घटना, जो पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति को उजागर करती है, की जाँच के लिए पार्टी का एक चार सदस्यीय पैनल गठित किया।

- भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा द्वारा गठित इस चार सदस्यीय पैनल में पूर्व केन्द्रीय मंत्री व पूर्व पुलिस कमिश्नर सतपाल सिंह के साथ मीनाक्षी लेखी और विपुल कुमार देव व मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं।

पैनल के सदस्यों हैं, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त सतपाल सिंह, पूर्व केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद विपल कुमार देव और मनन कुमार मिश्रा। यह पैनल घटना स्थल का दौरा करेगा और रिपोर्ट नड्डा को सौंपेगा।

गहलोत खुद ही मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होंगे : हनुमान बेनीवाल

बेनीवाल ने कहा कि प्रेमचन्द बैरवा व मदन राठौड़ ने धरना हटवाया था, पर परीक्षा नहीं टली

- राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के जाट समाज को आरक्षण दिलाने के लिए फिर से आंदोलन होगा। इसके लिए वे रविवार को भरतपुर जा रहे हैं।

लड़ाई और मुख्यमंत्री के खिलाफ षड्यंत्र जैसे मुद्दों पर बातचीत की। बेनीवाल ने कहा कि सरकार गिराने में गहलोत खुद शामिल होंगे, क्योंकि जिन बीजेपी वालों से उनकी बात हुई होगी, उनकी एमएलए वे ही देंगे। वे ऐसा पहले भी कर चुके हैं, इसलिए यह कोई अचरज वाली बात नहीं है। शेखावत और गहलोत के बीच बयानबाजी पर चूटकी लेते हुए बेनीवाल ने कहा कि दोनों एक ही हैं, पहले बात हो गई होगी आपस में, इसलिए अब बयानबाजी कर रहे हैं। मिलीभागत के खेल से प्रदेश का बंटोत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान भाजपा

ने कहा था कि वह एसआई भर्ती र्द करेगी, आरपीएससी का पुनर्गठन होगा। इसके झांसे में युवा आ गए थे, लेकिन अब पार्टी मुकर रही है। पिछले 66 दिन से धरना चल रहा है। कोई सुनवाई नहीं है। एक तरीख की मामले की सुनवाई है, अगर सरकार ने हमारे पक्ष में परिणाम नहीं दिया तो हम दिल्ली कूच करेंगे। बेनीवाल ने कहा कि आरएएस की मुख्य परीक्षा टालने के लिए उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने धरना हटवाया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि परीक्षा नहीं टाली गई। बेनीवाल ने कहा कि पूर्वी राजस्थान के जाट समाज को केन्द्र में आरक्षण

दिलाने के लिए फिर से आंदोलन किया जाएगा। इसके लिए वे कल भरतपुर जा रहे हैं। भरतपुर के डेहरा मोड़ पर कार्यक्रम रखा गया है। वहां बड़ा निर्णय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश के नौ राज्यों में जाट समाज को केन्द्र में ओबीसी आरक्षण से वंचित रखा गया है। इनमें राजस्थान में धौलपुर व भरतपुर शामिल हैं। राजस्थान में राज्य स्तर पर तो इन जिलों के जाट समाज को आरक्षण दे दिया गया, लेकिन केन्द्र के आरक्षण से वे आज भी वंचित हैं। इसको लेकर जाट आरक्षण संघर्ष समिति बनी है। नागौर सांसद बेनीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि एसीबी में वे ही अफसर लिए जा रहे हैं, जो पहले से जमकर भ्रष्टाचार करते रहे हैं। इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एसओजी के थे तो हमें विश्वास था कि हम एक साथ एक फ्री हैं। तीन मुस्लिम ले जाओ, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

इटली में हुआ ‘‘शोले’’ का प्रीमियर

इटली, 28 जून। बॉलीवुड फिल्मकार रमेश सिप्पी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘शोले’ का विश्व प्रीमियर इटली में बोलोग्ना के प्रतिष्ठित इल सिनेमा रिट्रोवाटो फेस्टिवल में किया गया। इसमें फिल्म का अनकट वर्जन दिखाया गया है।

फिल्म शोले की 50वैंी वर्षगांठ मनाने के लिए यह स्क्रीनिंग 27 जून को ओपन-एयर पिप्याज़ा मैग्रीगोर में हुई।

- इटली में हुए एक प्रतिष्ठित फिल्म फेस्टिवल में शोले का ‘‘अनकट वर्जन’’ दिखाया गया।

इस अवसर पर ‘शोले’ के निर्देशक रमेश सिप्पी ने कहा, क्या मैंने कभी सोचा था कि शोले इतनी दूर तक जाएगा। बिल्कुल नहीं ! मुझे याद है कि जब हम इसे बना रहे थे तो हमें विश्वास था कि हम एक अच्छी फिल्म बना रहे हैं। लेकिन एक ऐसी फिल्म जो सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)